औद्योगिक नीति में सुधारों के मामले से पिछड़े क्षेत्रों को होने वाले लाभ

1484. **श्री वीरेन्द्र कु० शाह:**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक नीति में व्यापक सुधार करके देश के पिछड़े क्षेत्रों को अधिकाधिक लाभ उपलब्ध कराने के प्रयास किये है ;

(ख) क्या यह सच है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा किये जाने के बाद देश के पिछड़े राज्यों को अपेक्षानुसार लाभान्वित नहीं किया जा सका है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(घ) क्या सरकार वर्तमान स्थिति को देखते हुए औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़े क्षेत्रों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए औद्योगिक नीति में और सुधारों की घोषणा करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) में : (क) से (ग) नई औद्योगिक नीति के तहत, सरकार बुनियादी विकास में उचित प्रोत्साहन और निवेश द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के छितराव को बढ़ावा देती है। किन्तु, किसी विशेष क्षेत्र/जिले के औद्योगीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। अधिकतर राज्य सरकारें पिछड़े क्षेत्रों धोगों को आकृष्ट करने के लिए कई प्रोत्साहन देती हैं।

(घ) और (ङ) वित्त विधेयक, 1994 में विशिष्ट पिछड़े जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए 5 वर्ष के करावकाश की घोषणा की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों सम्बन्धी समिति

1485. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये मंत्रिमण्डल सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है जो सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एककों के भविष्य के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों के सम्बन्ध में कई अन्य समितियों आदि से भी सुझाव मांगे थे;

(ग) यदि हां, तो उन समितियों या विशेषज्ञों या आयोगों की संख्या कितनी है जिनसे सरकार को उक्त अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में सिफारिशें प्राप्त हुई तथा इस प्रयोजनार्थ गठित की गई समितियों अथवा आयोगों का ब्यौरा क्या है और इनका गठन किन किन तिथियों को किया गया ;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) नवगठित समिति को कब तक अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।